फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 126 प्रभात जयपुर, रविवार 7 दिसम्बर, 2025 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

120 Bahadur, Paltan Legends Of Indian Courage

J. P. Dutta once told Col Bishan Singh, "Kahaniyan hum nahi banate, Colonel saab… aap log banate hain. Hum sirf unki awaaz ko buland karte hain."

A Respect Deserved

This day, 104 Tuskegee Airmen Arrested for Defying Segregation in the U.S. Army Air Corps

'इंडिगो एयरलाइन्स को अडानी ग्रुप को सौंपने की तैयारी में वर्तमान संकट उत्पन्न करवाया गया है'

विपक्ष द्वारा सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया जा रहा है

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 दिसंबर। देश भर में इंडिगो की उड़ानों में जो भारी गतिरोध उभरा है, वह हाल के समय में एक बड़ा विमानन संकट बन गया है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है, वह है जिम्मेदारी का पूरी तरह से अभाव। हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और आखिरी समय में फ्लाइट कैंसल करना यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रहा है, न तो सरकार, न एयरलाइन और न ही नियामक संस्था ने इस संकट की जिम्मेदारी लेने की ओर कदम उठाया है।

इंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और घरेलू यातायात का लगभग 60 प्रतिशत भार संभालती है, ने "संचालन संबंधी चुनौतियों" का हवाला देते हुए सामान्य बयान जारी किए हैं, लेकिन इन व्याख्याओं ने नुकसान के पैमाने को हल करने में बहुत कम मदद की है।

वहीं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने चुप्पी साध रखी है और स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि यात्रियों को देरी, फिर से बुकिंग और आपातकालीन यात्रा खर्चों के कारण हुए वित्तीय नुकसान का मुआवजा कौन देगा।

- **विपक्ष के अनुसार, अचानक तकनीकी खामियाँ उभर आईं, पायलैट्स की कमी उत्पन्न हो गई तथा शैड्यूल ब्रेकडाउन हो गए तथा इस फेलियर की जवाबदेही लेने को कोई अभी तक तैयार नहीं है, न तो एयरलाइन्स, न सरकार और और न ही रेग्युलेटर।**
- **विपक्ष का आगे यह तर्क है कि अडानी ग्रुप ने अपना शिकंजा एयरपोर्ट, प्रशिक्षण सुविधाओं व एविएशन सर्विस सैक्टर पर पहले ही फैला दिया है। अब वो इंडिगो एयरलाइन्स का टेक ओवर करने को तैयार है और यह वर्तमान संकट इंडिगो एयरलाइन्स में सुनियोजित तरीके से करवाया गया, जिससे इंडिगो एयरलाइन्स टेक ओवर के प्रस्ताव के लिए "सॉफ्ट" (मुलायम) हो जाए और टेक ओवर आसान शर्तों के तहत हो जाए।**
- **एक पुराने एविएशन विशेषज्ञ का इस बारे में कहना है कि एक एयरलाइन्स को इतना बढ़ने देना कि 60 प्रतिशत मार्केट उसे कब्जे में हो जाए तथा दूसरी ओर एविएशन सैक्टर के आधारभूत ढांचे पर इतना छा जाए कि सरकार की क्षेत्र में संतुलन बैठाने की क्षमता खत्म हो जाए, यह खतरनाक स्थिति है।**

विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि यह संकट सिर्फ संचालन संबंधी विफलता नहीं हैं, बल्कि यह एक ऐसा कृत्रिम संकट है, जिसे इंडिगो को अडानी ग्रुप को सौंपने के लिए खड़ा किया गया है। अडानी समूह तेजी से हवाई अड्डों, प्रशिक्षण सुविधाओं और विमानन सेवाओं में अपनी घुसपैठ बना रहा है।

तकनीकी समस्याओं, चालक दल की कमी और शेड्यूल में बदलाव की घटनाओं में अचानक वृद्धि ने संदेह उत्पन्न किया है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि यह अराजकता, विमानन क्षेत्र में एक बड़े रणनीतिक पुनर्संयोजन का हिस्सा हो सकती है।

विशेषज्ञ हैरान हैं और सरकार तथा नगर विमानन महानिदेशालय से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी किसी जोड़-तोड़ को आधिकारिक रूप से स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा? व्यवधानों का समय और पैमाना यह संदेह पैदा करता है कि इस क्षेत्र के दो प्रमुख शक्ति केन्द्र, देश की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीतालक्ष्मी सहित तीन सह आरोपियों की जमानत खारिज

जयपुर, 6 दिसंबर। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने आईटीएटी जयपुर बेंच में रुपए लेकर फैसले देने से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप मामले में, आरोपी सीता लक्ष्मी सहित वकील राजेन्द्र सिसोदिया व अन्य पक्षकार मुजम्मिल को जमानत से इनकार करते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मामले में अनुसंधान चल रहा है। ऐसे में इस स्तर पर आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।

- **सीतालक्ष्मी, वकील राजेन्द्र सिसोदिया और पक्षकार मुजम्मिल, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार करते हुए कहा, इन पर गंभीर आरोप हैं, जमानत नहीं दी जा सकती।**

आरोपी सीता लक्ष्मी सहित दोनों आरोपियों ने कोर्ट से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया था। इस मामले में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति के भोज में शशि थरूर का आमंत्रण फिर "विवादित" हुआ

शशि थरूर ने कहा, वे पर राष्ट्र मामलों के लिए गठित स्थाई संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, अतः, उन्हें आमंत्रित किया गया है, रूस के राष्ट्रपति को दिए गए भोज में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 दिसंबर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गर्व से याद किया कि 20 साल पहले जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वह आज जियापोलिटिकल सम्बंधों में कहीं अधिक सही साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ डिनर निमंत्रण पर भी प्रकाश डाला, जो दो दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आए थे।

थरूर ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार रात को उनकी उपस्थिति का कारण विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति (पार्लियामेटरी स्टैन्डिंग कमेटी ऑन एक्स्टरनल अफेयर्स) के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा किया गया कार्य था।

इस राजकीय डिनर, जिसे थरूर ने "उत्कृष्ट बताया, के बाद उन्होंने एनडीटीवी के सीईओ तथा एडिटर-इन-चीफ राहुल कँवल से कहा, "मैं काफी समय बाद राष्ट्रपति भवन आया हूँ। कुछ वर्षों तक मुझे लगता था कि उनका रुख थोड़ा अलग है। ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने थोड़ा खुलने और दूसरों की बात सुनने का निर्णय लिया है और साफ बात तो यह है कि चूँकि विदेशों के साथ वही रिश्ते तो होते हैं, जिनसे हमारी संसदीय स्थायी समिति संबंधित होती है, इसलिए यहां की बातचीत तथा माहौल आदि को जानना उपयोगी है। इस कारण, मैं यहां आने पर बहुत प्रसन्न हूं। बस यही कारण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।"

कांग्रेस के कई नेताओं, जैसे पवन खेड़ा और जयराम रमेश, ने इस पर सवाल उठाया कि पार्टी सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राजकीय डिनर के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

ये प्रतिक्रियाएँ तब आईं, जब थरूर ने शुक्रवार को संसद के बाहर संवाददाताओं को यह बताया कि उन्हें राजकीय डिनर का निमंत्रण मिला है

- **थरूर ने इस विषय में आगे कहा कि वे भोज में अवश्य जाएंगें, क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों व उनकी टीम के लोगों तथा भारतीय टीम के बीच हुए वार्तालाप को प्रत्यक्ष देखकर उनको, उनके संसदीय समिति के अध्यक्ष के बतौर काम में मदद मिलेगी।**
- **थरूर की भोज में मौजूदगी को जयराम रमेश व पवन खेड़ा ने उचित नहीं माना। उनके अनुसार यह उपस्थिति, कांग्रेस पार्टी के, सरकार के प्रति घोषित रूख, सोच व नीति के खिलाफ है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनमाने हवाई किराए पर केन्द्र सरकार सख्त, किराए पर कैप लगाया

लेकिन इससे सरकार की जवाबदेही पूरी नहीं हो जाती

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को इंडिगो के सभी घरेलू उड़ानों में भारी देरी और निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) के बाद, एयरलाइन टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए हवाई किराये की सीमा निर्धारित करने की घोषणा की।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने इस बात को गम्भीरता से लिया है कि मौजूदा संकट के दौरान कुछ एयरलाइनों द्वारा अत्यधिक उच्च हवाई किराए वसूलने की शिकायतें आ रही हैं। बयान में कहा गया है, "यात्रियों को किसी भी प्रकार के अवसरवादी मूल्य निर्धारण से बचाने के लिए, मंत्रालय ने अपनी नियामक शक्तियों का उपयोग करते हुए, सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और यथोचित किराए सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।"

मंत्रालय ने कहा, "एक आधिकारिक निर्देश सभी एयरलाइनों को जारी किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े आदेश दिए गए हैं कि निर्धारित किराया सीमा का पालन किया जाए। ये सीमाएं तब तक

- **इंडिगो एयरलाइन्स के संकट के दौरान अन्य एयरलाइन्स द्वारा भारी किराया वसूली की शिकायतों के बाद केन्द्र सरकार ने यह कदम उठाया।**
- **नागर विमानन एवं उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइन्स को निर्देश दिया है कि किराए पर लगी सीमा का सख्ती से पालन किया जाए।**
- **मंत्रालय ने कहा कि वह किराए के स्तर पर बारीकी से नज़र रखेगा और एयरलाइन के डेटा व ऑनलाइन प्लेटफार्म्स के डेटा के बीच तालमेल करेगा।**
- **मंत्रालय ने एक पृथक बयान जारी कर इंडिगो को हिदायत दी कि जल्द से जल्द सभी यात्रियों को किराया राशि लौटा दें।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाबू लाल कटारा को केन्द्रीय कारागार में शिफ्ट किया

जयपुर, 6 दिसंबर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने अदालत को जयपुर जिला जेल में अपनी हत्या होने या डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की बात कही है। वहीं, ईडी कोर्ट

- **वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपरलीक में आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबू लाल कटारा ने अपनी हत्या की आशंका जताई, साथ ही डिप्रैशन में आकर आत्महत्या करने की बात कही। इसीलिए उन्हें जिला जेल से केन्द्रीय कारागार में शिफ्ट किया गया है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिज़र्व बैंक द्वारा "रैपो रेट" (ब्याज दर) घटाना "डिमांड" को चमकायेगा

पर, अगर रूपए का मूल्य घटता रहा, डॉलर की तुलना में, तो यह आशावादी कदम, खोखला भी साबित हो सकता है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, ग्रोथ को सपोर्ट करने की दिशा में एक बदलाव है, लेकिन यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति अभी भी स्थिर नहीं है। इस कटौती से घरों और बिज़नेस के लिए उधार लेने की लागत कम हो सकती है, लेकिन यह फाइनेंशियल स्थिरता, करेंसी मैनेजमेंट और महंगाई के रास्ते की स्थिरता के बारे में भी कई सवाल खड़े करता है। कुल मिलाकर, यह सावधानी भरी उम्मीद का संकेत है, लेकिन लापरवाही का नहीं।

चिंता का पहला कारण कमज़ोर होता रुपया है, जो पॉलिसी घोषणा से ठीक एक दिन पहले अपने नए निचले स्तर पर फिसल गया था। रेट कटौती से भारत और अमेरिका की ब्याज दरों के फर्क में कमी आती है, जो करेंसी पर दबाव बढ़ा सकती है। अगर अमेरिकी फेडरल रिज़र्व अपनी रेट कटौती को आगे टालता है, जिसकी संभावना बाज़ारों में बढ़ रही है, तो रुपए पर गिरावट का दबाव लगातार बना रह सकता है। इससे आर.बी.आई के लिए, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन (आयातित महंगाई) को नियंत्रित रखना मुश्किल होगा। कमज़ोर रुपया, तेल, फर्टिलाइज़र और अन्य ज़रूरी इंपोर्ट को महंगा कर देता है, जिससे महंगाई में मिली हाल की राहत फिर उलट सकती है।

आर.बी.आई. ने महंगाई में नरमी को इस कटौती का मुख्य आधार बताया है, लेकिन आगे का रास्ता जोखिमों से खाली नहीं है। खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई एक लगातार बनी रहने वाली अनिश्चितता है, खासकर जबकि, बारिश के पैटर्न में असमानता और जलवायु से संबंधित रुकावटें ज़्यादा बार होने लगी हैं। सेंट्रल बैंक के अनुमान इस साल खाद्य कीमतों को स्थिर मानकर बनाए गए हैं, लेकिन सप्लाई में किसी भी तरह की रुकवाट उसे अपना रुख फिर बदलने पर मजबूर कर सकती है। अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि भारत में महंगाई के चक्र ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता वाले होते हैं, और कुछ महीनों के अच्छे आंकड़े लंबे समय के ट्रेंड की गारंटी नहीं देते हैं।

दूसरी बड़ी सावधानी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी से संबंधित है। आमतौर पर रैपो रेट घटने

- **ब्याज दर घटने से, पैसा ज्यादा आता है मार्केट में तथा इससे ग्राहकी भी बढ़ती है। पर, यह चक्कर पूरा होने के लिए जरूरी है कि बाहरी माहौल में स्थिरता रहे।**
- **पर, अगर अमेरिका ने ब्याज दर नहीं घटाई और विदेशी इन्वेस्टर भारत से डॉलर को निकालकर अमेरिकी स्टॉक में लगाते रहे तो रिज़र्व बैंक के लिए रूपए को गिरने से रोकना पहली प्राथमिकता हो जाएगी।**
- **इस स्थिति में रेट घटाने से मार्केट चमकेगा नहीं, बल्कि धूमिल होकर रह जाएगा।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केस तय समय सीमा में खत्म होने चाहिए

नई दिल्ली, 06 दिसंबर। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को निपटाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय न्यायिक नीति उनकी पहली प्राथमिकता है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान बोलते हुए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मेरी पहली प्राथमिकता एक तय समयसीमा और एक एकीकृत राष्ट्रीय न्यायिक नीति (यूनिफाइड नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी) बनाना है ताकि लंबित मामलों

- **देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इसके लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक को भारी खतरा पैदा हुआ, हुमायूं कबीर के रूप में

हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के पुराने वफादार मुस्लिम इस्लामिक नेता थे, जिसने अब बगावत कर, ममता बनर्जी को दहशत में ला दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने ही किए का परिणाम झेल रही हैं।

उनके एक भरोसेमंद साथी, हुमायूं कबीर, जो अब तक ममता के क़रीबी माने जाते थे, ने उनके खिलाफ़ बग़ावत कर दी है। यह ममता के लिए एक ऐसा बड़ा राजनीतिक जाल है, जैसा अब तक उनके सबसे बड़े भाजपा आलोचक भी नहीं बिछा सके थे।

हुमायूं कबीर ने आज, 6 दिसंबर को, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की याद में मुर्शिदाबाद ज़िले में, बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने यह सब तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की अवहेलना करते हुए और ममता बनर्जी के प्रति अपनी अवज्ञा व्यक्त करते हुए किया।

यह याद दिलाना ज़रूरी है कि यही वह मुर्शिदाबाद ज़िला है, जहाँ कुछ समय पहले मुस्लिम भीड़ ने एक पिता-पुत्र को उनके घर से घसीटकर बेरहमी से मार दिया था। बाप-बेटे की "गलती" यह थी कि वे हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाते थे। न कोई गिरफ़्तारी हुई, न किसी पर मुकदमा चला।

घटना के समय, कबीर ने धमकी दी थी कि वे बंगाल के हिंदुओं की हत्या कर उनकी लाशें बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वे मुर्शिदाबाद को हिंदू-मुक्त कर देंगे। अब वही कबीर, एक इस्लामिक राज्य की अपनी आकांक्षा में, ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे रहे हैं। यह ममता बनर्जी और, उनके ज़रिए, पूरी तृणमूल कांग्रेस और बंगाल में उनके प्रभुत्व पर एक सीधा निजी हमला है। यह स्थिति कभी न कभी आनी ही थी, ममता बनर्जी की असीमित तुष्टिकरण नीति के कारण।

कबीर जल्द ही अपनी अलग इस्लामी पार्टी बनाने की धमकी दे रहे हैं। माहौल पहले ही तैयार कर लिया गया है और उन्होंने ऐसे तत्वों की सहानुभूति हासिल कर ली है।

अब तक, कुछ अखिल भारतीय मुस्लिम नेताओं ने बंगाल में आने की धमकी दी थी। हैदराबाद के ओवैसी ने भी कई बार बंगाल के मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। ममता बनर्जी हर बार बस यह कहकर बात टाल देती थीं कि ओवैसी हैदराबादी हैं: "उनका घर हैदराबाद है।"

- **हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में एक "बाबरी मस्जिद" के निर्माण की नींव रखी 6 दिसंबर को। उन्होंने अपने इस कृत्य से ममता बनर्जी से बड़ा इस्लामपरस्त नेता होने का दावा किया।**
- **अब तक ममता जी ने अपने आपको सबसे प्रबल इस्लाम समर्थक नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रखा था तथा मुसलमानों ने भी उन्हें जमकर वोट दिए हर चुनाव में।**
- **कई मुस्लिम नेताओं ने बंगाल में पैर जमाने की कोशिश की, पर किसी को सफलता नहीं मिल पाई। उदाहरण के लिए ओवैसी ने जब काफी कोशिश की तो ममता जी ने उन्हें एक ही वार में उड़ा दिया, यह कहकर कि वह हैदराबादी हैं उन्हें वहीं रहने दो।**
- **पर, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद का है, परस्त हैं, उसने मुर्शिदाबाद को हिंदू मुक्त करने जैसा खतरनाक नारा दिया है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति और प्र.मंत्री ने अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी

नयी दिल्ली, 06 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित, कई प्रमुख लोगों ने शनिवार को संसद भवन परिसर में डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर को

- **प्र.मंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, हम बाबा साहेब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर स्मरण करते हैं, न्याय व समानता के उनकी सोच सदैव भारत का मार्गदर्शन करती रहेगी।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)